

विचार बिन्दु

मनुष्य का कर्तव्य है कि वह उदार बनने से पहले त्यागी बने। –डिंकस

नई पीढ़ी कटघरे में क्यों?

क्या हमारी नई पीढ़ी सचमुच गैर जिम्मेदार है? दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए शिक्षामंत्री हटाओ आंदोलन के बाद यह प्रश्न फिर से चर्चा के केंद्र में है। असल में यह आंदोलन अनेक ऐसे प्रश्न छोड़ गया है, जिन पर लंबे समय तक चर्चा होती रहेगी। इस आंदोलन ने एक विरोधाभास भी सामने रखा। कुछ युवाओं की अमर्यादित अभिव्यक्तियों आलोचना का कारण बनीं, तो उन्हीं युवाओं का अनुशासन, साहस और संगठन-क्षमता व्यापक सराहना का विषय भी बनी। हमारा समय तोखे ध्रुवीकरण का है। ऐसे समय में किसी एक या किन्हीं कुछ घटनाओं के आधार पर किसी पीढ़ी का मूल्यांकन करना उचित नहीं कहा जाएगा।

अगर आप थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि दुनिया के हर देश और हर काल में वर्तमान पीढ़ी अपनी उत्तराधिकारी पीढ़ी से असंतुष्ट रही है। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों और रोमन लेखकों ने युवाओं की खूब शिकायतें की हैं। असल में तो हर युग में बुजुर्गों ने युवाओं के प्रति अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। उनकी मुख्य शिकायतें ये रही हैं कि युवा मेहनत से कतराते हैं, वे अनुशासनहीन हैं, बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, उनके मन में परंपराओं के प्रति सम्मान नहीं है वगैरह। आजकल भारत में बड़ों से यह सुनना आम है कि युवा हर समय मोबाइल में खोये रहते हैं और कोई सार्थक काम करने की बजाय रोलें देखते रहते हैं। भारतीय बुजुर्गों की आम राय यह है कि वे बहुत अच्छे थे और युवा उतने अच्छे नहीं हैं। हमारे ज़माने में.... उनका बेहद प्रिय प्रारम्भिक कथन होता है। रोचक बात यह है कि हर पीढ़ी की अपनी बाद वाली पीढ़ी के लिए ऐसी ही राय रही है।

अगर हम आज की युवा पीढ़ी को देखें और उसका एक तटस्थ आकलन करने का प्रयास करें तो हम पाते हैं कि जो आरोप उस पर लगाए जाते हैं, वे एक सीमा तक सही भी हैं। मसलन यही कि उसमें धैर्य की कमी है। वह बहुत जल्दी सब कुछ हासिल कर लेना चाहती है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि इसमें बुराई क्या है? जो चीज़ हमारी पीढ़ी को बीस साल में हासिल हुई उसे अगर बाद वाली पीढ़ी पांच साल में हासिल करना चाहती है और कर भी रही है, तो इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए, न कि आलोचना। इस पीढ़ी पर आरोप लगाया जाता है कि इसे संस्थाओं पर, चाहे वे सामाजिक हों, धार्मिक हों, सांस्थानिक हों, प्रशासनिक हों, कोई भी हो- कम भरोसा है। बात सही है। लेकिन विचार कीजिए कि क्या संस्थाओं ने खुद को ऐसा बनाया है कि उन पर आँख मूंदकर भरोसा किया जाए? अगर नहीं, तो उन पर कम भरोसा रखना कौन-सा गुनाह हो गया? नई पीढ़ी की डिजिटल निर्भरता की बहुत आलोचना होती है। उंडे मन से सोचिए, क्या इससे उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है? कब तक हम केवल परंपरा के नाम पर नवाचारों से कतराते रहेंगे?

इसी संभावनाशील युवा पीढ़ी का एक हिस्सा गैर जिम्मेदार, अराजक, और उच्छ्वल भी है। उसमें त्वरित सफलता की इतनी तीस्र आकांक्षा है कि असफलता का सामना करने का धैर्य जैसे रह ही नहीं गया है। सोशल मीडिया ने तुलना और त्वरित मान्यता की ऐसी संस्कृति बना दी है कि उसके अभ्यस्तों को संघर्ष की लम्बी यात्रा असहनीय लगने लगती है। बहुत सारे युवा ऐसे भी हैं जो अपने आपास के यथार्थ से एकदम निलिप्त हैं और उनका एकमात्र संरोधक अपना पैकेज है। ऐसे भी युवा हैं जिसके लिए नैतिकता अब कोई मूल्य नहीं है। लेकिन पूरी युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व ऐसे युवा नहीं करते हैं।

पूरी दुनिया में पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता और मानसिक स्वास्थ्य जैसे बड़े मुद्दों पर युवा पीढ़ी ने जो सक्रियता दिखाई है वह हम सबको आह्लादित करती है। भारत में भी समय-समय पर विभिन्न मुद्दों पर इसी पीढ़ी ने खतरे उठाकर भी अपनी आवाज़ बहरे कानों तक पहुंचाई है और वर्तमान नीट परीक्षा वाले आंदोलन में युवाओं ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है।

के आंदोलन और वर्तमान नीट परीक्षा वाले आंदोलन में युवाओं ने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। नीट वाले आंदोलन में अनुशासन का बने रहना, लड़कियों के प्रति दुर्व्यवहार का एक भी मामला न होना, सत्ता की निरंकुशता का सामना उच्छ्छ हास्यबोध और रचनात्मकता से करना, और पूरे आंदोलन स्थल को यथासंभव साफ़ रखना ऐसे बिंदु हैं जिन्हें सर्वत्र सराहा गया है। और ऐसा नहीं है कि यह पीढ़ी केवल आंदोलनों में ही अपनी क्षमता प्रदर्शित करती है। भारत की स्टार्टअप संस्कृति, तकनीकी नवाचार, ऑनन-सोर्स समुदाय, स्वयंसेवा, रक्तदान और आपदा-राहत जैसे असंख्य क्षेत्रों में उसकी ऊर्जा और रचनात्मकता साफ़ दिखाई देती है। कला संस्कृति के क्षेत्र में भी इनका योगदान उल्लेखनीय और सराहनीय है।

यहीं ज़रा ठहर कर खुद से एक सवाल कर लिया जाना चाहिए। हम युवा पीढ़ी का आकलन करते हैं, इस पीढ़ी को अक्षम, अकर्मण्य, आलसी, गैर जिम्मेदार वगैरह ठहराते हैं। उस पर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन क्या हम इन्हें जिम्मेदारी भी देते हैं? क्या हम इन्हें स्वतंत्र रूप से कुछ करने की आजादी भी देते हैं? घर-परिवार में, शैक्षिक संस्थाओं में, समाज में, राजनीति में-कहां हम इन्हें खुलकर कुछ करने देते हैं? राजनीति में वृद्धजन युवाओं के लिए जगह खाली ही नहीं करते हैं। घर-परिवार में कोई किशोर या युवा क्या पढ़ेगा, यह उसके बजाय उसके मां-बाप तय करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई अपनी पसंद से विवाह करना चाहे तो उसे सुनना पड़ता है, क्या हमने तुम्हें इसी दिन के लिए पाठ पोस कर बड़ा किया था? आजीविका के मामले में हम कभी उसे स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देते। अगर वह किसी कला या खेल में रुचि लेता है तो हम उसे धिक्काते हैं और पढ़ाई में मन लगाने के लिए धकेलते हैं। वह गायक बनना चाहता है हम उसे आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा भेज देते हैं। ज़रा सोचिये, जिस देश और समाज में बीस-पच्चीस साल के युवा की ज़िंदगी के सारे फैसले उसके पचास-साठ साल के माता-पिता ही करें, वहां युवाओं से किस जिम्मेदारी की अपेक्षा की सकती है? और क्यों की जानी चाहिए? हम उन्हें स्वतंत्र रूप से चलने-फिरने तो देते नहीं और फिर कहते हैं कि उनमें आत्मविश्वास नहीं है।

इतना सब कह देने के बाद यह भी कहना जरूरी है कि हर पीढ़ी अपना निर्माण खुद करती है। वह अपनी राह और मंजिल खुद चुनती है, बशर्ते उसे ऐसा करने दिया जाए। हमारा स्वभाव यह है कि हम अपनी बाद वाली पीढ़ी के हाथ पांव बांध कर उस पर आरोप लगाने में सुख प्राप्त करते हैं कि वह दौड़ नहीं रही है। हम उससे जिम्मेदारी की अपेक्षा तो करते हैं लेकिन उस जिम्मेदारी सौंपने की हिम्मत नहीं दिखाते। हम उसके लिए रास्ते तय करते हैं, उसकी मंजिल निश्चित करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो रही है। सच तो यह है कि हर पीढ़ी अपने से बाद वाली पीढ़ी को वही देती है जो उसके भीतर होता है - विश्वास या भया। यदि हम सक्षम युवाओं का समाज चाहते हैं तो उन्हें नियंत्रित करने से अधिक उन पर विश्वास करना सीखना होगा।

—अश्विनी संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

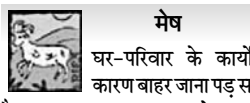
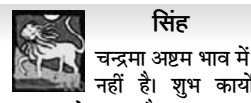
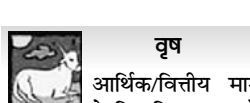
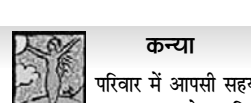
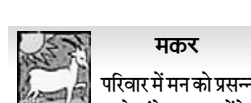
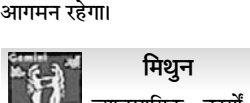
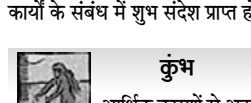
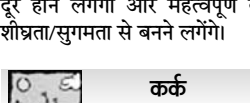
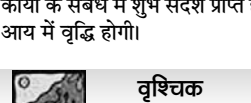
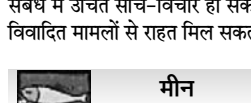
राशिफल सोमवार 3 अगस्त, 2026

सावन मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, रविवार, विक्रम संवत 2083, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 10:00 तक, सुकर्मा योग रात्रि 9:14 तक, कौलव करण दिन 11:03 तक, चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-मीन, मंगल-मिथुन, बुध-मिथुन, गुरु-कर्क, शूक्र-कन्या, शनि-मीन राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज प्रथम सावन वन सोमवार, नाग पंचमी (राज.) है। आज हरदेव पूजा है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 7:35 तक, शुभ 9:14 से 10:54 तक, चर 2:12 से 3:51 तक, लाभ-अमृत 3:51 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:56, सूर्यास्त 7:10

	मेघ घर-परिवार के कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। समय अनावश्यक खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।		सिंह चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब होने का भय बना रहेगा। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।		धनु घर-परिवार में आपसी मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।
	वृष आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा।		कन्या परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।		मकर परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।
	मिथुन व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चन दूर होने लगेगी और महत्वपूर्ण कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगेंगे।		तुला नौकरपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। आय में वृद्धि होगी।		कुंभ आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।
	कर्क नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। धार्मिक-मानसिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा संभव है।		वृश्चिक परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। आज अनापयक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।		मीन व्यावसायिक कार्यों से संबंधित योजना बनेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। नौकरपेशा व्यक्तियों का मानसिक तनाव दूर होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



रामपाल जाट

दोहरे मापदंड:- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री सुरेश गोपी द्वारा लोकसभा में 7 अगस्त 2025 को दिए गए उत्तर के अनुसार 2014-15 से जून 2025 तक इथेनॉल मिश्रण से 238 लाख मैट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन हुआ, एवं 1,40,000 करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। भारत के कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का निर्धारण किए बिना ही दीवार घड़ी के पेंडुलम की भांति चलना दोहरे मापदंडों का परिचायक है।

भारत में वर्ष 2003 मे पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय नीति आरंभ हुई। वर्ष 2014 तक पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की मात्रा 1.5 प्रतिशत रही, वर्ष 2014 जून के बाद मिश्रण की मात्रा 5 से 10 प्रतिशत कर दी गई, 2018 में नई नीति तैयार की गई, जिसके अनुसार मिश्रण की मात्रा को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की अवधि 2030 निर्धारित की गई, इसके 5 वर्ष पूर्व मार्च 2025 में मिश्रण की मात्रा 19.2 प्रतिशत कर दी गई, जो 2025-26 में 20 प्रतिशत हो गई। इस नीति में ब्राजील की भांति गाड़ियों के अनुकूल इंजन तैयार करने, मूलभूत अवसंरचना को सुदृढ़ करने, और जनसामान्य को विकल्प देने का प्रावधान नहीं किया गया।

राजनेताओं की चीनी मिलों को घाटे से बचाने के लिए इथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देने की नीति पर वर्ष 2013 के पहले विचार आरंभ हो गया था। माह जून 2014 के उपरांत सरकारी प्रभाव से इस नीति के पंख लग गए। इसी को न्यायोचित

ठहराने के लिए अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाकर मालामाल करने का राग अलापना आरंभ हो गया।

देश में प्रदूषण रहित ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जानवर था, जो आधुनिक प्रौद्योगिकी के नाम पर पार्श्व में धकेल दिया गया। ऊर्जा के अन्य स्रोतों की अपेक्षा इथेनॉल को रामबाण औषधि के रूप में मान लिया गया। इसी से इथेनॉल निर्माण इकाइयों को मूल्य निर्धारण एवं विपणन की चिंता से मुक्त कर दिया गया। उन पर संरक्षण एवं सहायता के रूप में सरकारी कृपा बरसना आरंभ हो गई। इथेनॉल से अपेक्षित अच्छे विकल्पों के विचार पर ग्रहण लग गया। राजनीति में स्वयं को लुट से दूर रखने का संकल्प व्यक्त करने वाले भी ऐसे परिवेश में लुकी की धारा में बह जाते हैं। इससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होने लगती है। लालच को त्यागे बिना स्वयं की श्रेष्ठता को प्रमाणित करने में वे अपनी बुद्धि एवं शक्ति का उपयोग करने लग जाते हैं। यह कागज के फूलों में सुगंध उत्पन्न करने जैसा ही निरर्थक श्रम है।

जिस मक्का की इथेनॉल निर्माण में 72 प्रतिशत भागीदारी रही है, उस मक्का को 'न्यूनतम समर्थन मूल्य' 2400 रुपए प्रति क्विंटल होते हुए भी मक्का उत्पादक किसानों को एक क्विंटल के दाम अधिकतम 1800 रुपये प्राप्त हुए। जबकि इथेनॉल निर्माण इकाइयों ने उत्पादन खर्च की गणना 2400 रुपए प्रति क्विंटल के आधार पर की थी, उसी के अनुसार इथेनॉल निर्माण इकाइयों को एक लीटर इथेनॉल के दाम 71.86 रुपये प्राप्त हुए। किसानों को प्राप्त होने वाले अधिकतम दामों के आधार पर गणना करने पर एक लीटर के दाम 54.52 रुपए प्राप्त होने चाहिए थे। इसी प्रकार 100 प्रतिशत कटे चावलों की स्थिति है। जिसका घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,183 रुपए प्रति क्विंटल है, इथेनॉल निर्माण इकाइयों के लिए 100 प्रतिशत कटे चावल का मूल्य 2320 से लेकर 2390 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। एक नवंबर 2026 से 31 प्रतिशत अक्टूबर 2027 तक 72 लाख मैट्रिक टन चावल इथेनॉल कंपनियों के लिए आरक्षित किया गया है, इसके पूर्व 2025-26 में इसी अवधि में 52 लाख मैट्रिक टन चावल आरक्षित किया गया था। नीति आयोग तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की, रोड मैप फार् एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020-25 के प्रतिवेदन के अनुसार गन्ने से एक लीटर इथेनॉल तैयार करने

में 3000 लीटर पानी का उपयोग होता है। मेरी विरासत में कम पानी वाली फसलों को प्रोत्साहित कर रही है, दूसरी ओर रोडमैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया की ओर दौड़ रही है।

विकल्प- यह सही है कि 85 प्रतिशत कूड़ विदेशों से आयात हो रहा है, होर्मुज बंद जैसी घटनाओं के बाद आयात की निर्भरता को कम करना, विदेशी मुद्रा को बचाना तथा पर्यावरण की रक्षा करना सामयिक आवश्यकता है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा, भूगर्भ से ऊर्जा, जानवरों से प्राप्त ऊर्जा जैसे श्रेष्ठतर विकल्पों के उपयोग पर विचार किए बिना देश की खाद्य सुरक्षा की बलि देना उचित नहीं हो सकता।

जिस प्रकार इथेनॉल निर्माण इकाइयों के लिए निश्चित मूल्य प्रदान करने एवं विपणन की चिंता से मुक्त रखने की नीति तैयार की गई है, इस प्रकार की नीति इथेनॉल निर्माण में काम करने वाले मक्का, चावल जैसी कृषि उपजों के लिए नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत गन्ना को आवश्यक वस्तु घोषित कर गाा नियंत्रण आदेश प्रसारित किया गया है, उस प्रकार से मक्का को आवश्यक वस्तु के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। इसके अभाव में भी मक्का उत्पादक किसानों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी वंचित रहना पड़ता है।

कृषि उपजों को लाभकारी मूल्य दिलाने की दिशा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी श्रेष्ठ उपाय है। सरकारी नीतियां उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए तैयार नहीं की गई हैं। बल्कि वर्ष 1968 में कृषि मूल्य नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटीड मूल्य के रूप में वर्णन किया गया, उसका क्रियान्वयन 58 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी नहीं हो पाया है। इसी अनुक्रम में 12 जुलाई 2022 को गठित समिति के उपसमूह ने 21 अप्रैल 2023 को न्यूनतम समर्थन मूल्य को आरक्षित मूल्य श्रेणी में रखकर मंडियों में नीलामी बोली का आरंभ न्यूनतम समर्थन मूल्य से करने संबंधी अनुशंसा की हुई है। उस समिति का प्रतिवेदन अभी तक भी प्रकाशित नहीं किया गया है। सरकार द्वारा अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने का मंतव्य किसानों का कल्याण करना नहीं बल्कि किसानों के नाम पर इथेनॉल निर्माण करने वाले धनपतियों को लाभान्वित करना है। इथेनॉल को आइसोब्यूटेनॉल में बदलकर ही डीजल में उपयोग किया जा सकता है। अब भारत में डीजल में भी 15 प्रतिशत

आइसोब्यूटेनॉल मिलावट करने की तैयारी चल रही है। दूसरी ओर भारत 1.5 करोड़ टन का पेट्रोल का फ्रांस, नीदरलैंड सहित अनेक देशों को निर्यात करता है, उसमें इथेनॉल मिश्रण वाला पेट्रोल नहीं है वरन शुद्ध पेट्रोल है। यदि मिश्रण श्रेष्ठ है तो निर्यात में भी भारत सरकार बहुत लेनी चाहिए।

एथेनॉल मिश्रण का प्रयोग करने के लिए वाहनों के इंजन के प्रौद्योगिकी का परीक्षण करना पूर्ववर्ती शर्त है। ब्राजील ने 10 से 30 प्रतिशत की यात्रा पूरी करने में 50 वर्ष का समय लगाया, भारत में 5 से 20 प्रतिशत तक की यात्रा 6 वर्ष में ही पूरी कर ली। परिवहन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में विक्रय किए गए 10 में से 7 वाहन 80:20 मिश्रण के अनुकूल नहीं थे, कारों और दो पहिया वाहनों में 3 प्रतिशत से भी कम वाहन इस मिश्रण के अनुकूल थे। मंत्रालय के वाहन पोर्टल के अनुसार 2025 के पूर्व विक्रय किए गए 1.37 करोड़ दोपहिया वाहनों में से 52 लाख तथा 33.6 लाख कारों में से 9 लाख कार ही इस मिश्रण के अनुकूल हैं। इसी प्रकार दो पहिया वाहनों में 72.5 प्रतिशत, तीन पहिया वाहनों में 71.6 प्रतिशत, कारों में 72.2 प्रतिशत, हल्के मालवाहक वाहनों में 66.6 प्रतिशत इस मिश्रण के अनुकूल नहीं हैं। वर्ष 2023 से पहले निर्मित वाहनों में से तो कार एवं दोपहिया कोई भी एथेनॉल मिश्रण के अनुकूल नहीं है। पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में स्वीकार किया है कि सरकार ने इस तथ्य का आकलन नहीं कराया कि देश में कितीन प्रतिशत गाड़ियां 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण के अनुकूल हैं। इसके बिना ही 20 प्रतिशत मिश्रण से गाड़ियों के इंजन को क्षति के संबंध में आधिकारिक सूचना प्राप्त नहीं होना दर्शाया है। यद्यपि इस उत्तर में 3 से 5 प्रतिशत माहलेज कम होने को स्वीकारा है। सरकार द्वारा अष्ट्र धन्यों के आधार पर 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण को सही की संज्ञा देने से सरकार की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ जाती है।

वर्ष भर भारत में 300 से अधिक दिनों तक सूर्य की असीम ऊर्जा प्राप्त होती है। 120 से अधिक देशों के समूह इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भारत नेतृत्व कर रहा है। वर्ष 2025 में नयी सौर को जोड़कर 38 गीगावाट सौर क्षमता हो गई, जो अमेरिका के 35 गीगावाट से अधिक है। इस प्रकार देश की कुल सौर क्षमता 150 गीगावाट से अधिक हो चुकी है। पेट्रोल डीजल से चलने वाले उपकरणों में सौर ऊर्जा का उपयोग करने से 10

करोड़ बैरल तेल की मात्रा घट सकती है, जिससे लगभग 716 अरब से 1,050 अरब रुपये विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है। सौर से प्राप्त अनंत ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए विकल्प ही नहीं सामयिक राष्ट्रीय आवश्यकता है। प्रत्येक छत पर सौर उपकरणों की स्थापना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में छोटा किंतु निर्णायक कदम हो सकता है। यह विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने का श्रेष्ठ उपाय है, यह होमोज अलडमरूमध्य की निर्भरता से छुटकारा दिलाने की दिशा में कारगर सिद्ध हो सकता है। वर्ष 2025 में 2.3 टेरावाट घंटे की सौर ऊर्जा को ग्रिड की क्षमता के अभाव में छोड़ना पड़ा था, जिसे जिसे केंद्र सरकार ने संसद में स्वीकार किया है, उसमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार अप्रैल से जून 2026 के मध्य 8,133 गीगावाट घंटा जोड़ब्यूचर शोर बिकली का उत्पादन रोकना पड़ा, सबसे अधिक कटौती मई महीने में 3,235 जोड़ब्यूचर में हुई, ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन रोकने की यह स्थिति सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़ा करती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर ऊर्जा क्षेत्र में छलांग लगाने की क्षमता का तदनुकूल पूरे मन से उपयोग नहीं करने का स्पष्टीकरण सरकार से अपेक्षित है। परंपरागत रूप से पशुधन का ऊर्जा के रूप में उपयोग तो अनुभव सिद्ध प्रमाण है। 'जन -जंगल- जमीन -जानवर' आधारित सर्वसुलभ- प्रदूषण रहित ढांचे को युगानुकूल तैयार करने में आधुनिकता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है।

देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता देने, पानी के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, भारतीय संविधान में प्रदत्त सम्मान पूर्वक जीवनयापन के लक्ष्य को प्राप्त करने के संदर्भ में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के नाम पर सरकारों ने उपेक्षा ही की है। देश की आर्थिक स्थिति सुधार करने, कूड़ ऑयल पर निर्भरता कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने, प्रदूषण को रोकने एवं पर्यावरण को मानव जीवन में अनुकूल रखने, स्वतंत्रता के स्थायित्व के लिए खाद्य सुरक्षा को वर्ययता